ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 ईमेल-bsmirgae@gmail.com

---

समाज में गैर-बराबरी हिंसा का सबसे बड़ा कारणः मेधा पाटकर

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान कॉंग्रेस का अधिवेशन में वक्ताओं ने रखे विचार

वर्धा दि. २८ दिसंबर २०११ : समाज में फैल रही हिंसा गैर-बराबरी का सबसे बड़ा कारण है। समाज से न्याय की संकल्पना धीरे-धीरे लुप्त होते जा रही है। संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी खत्म किया जा रहा है। इस आशय के विचार नर्मदा बचाव आंदोलन की प्रणेता प्रख्यात समाजसेवी मेधा पाटकर ने हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में व्यक्त किए । वह विश्वविद्यालय में भारतीय समाज विज्ञान कॉंग्रेस के ३५ वें अधिवेशन के

दूसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में बोल रही थी । इस दौरान मंच पर मीडियाविद प्रो. रामशरण जोशी, विनायक सेन, एम.पी. परमेश्वरन, प्रो. राजकिशोर उपस्थित थे । सुलभा ब्राह्मे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

मेधा पाटकर ने हाल में जारी हुए आंकड़े का संज्ञान में लाते हुए बताया कि सरकार ने कारपोरेट जगत के ३.५ करोड़ रूपए का कर माफ कर दिया। जबकि आम आदमी जो खेती पर अपने जीवन का निर्वाह करता है उसे अपने उत्पादन का समर्थन मूल्य पाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है।

उन्होंने आंकड़ों की विवेचना करते हुए आगे बताया कि एक उद्योगपति १ सेकेंड में ४० लाख रूपए कमाता है तो खबरों में सुर्खियां पाता है । दूसरी ओर एक किसान महज ४० हजार रूपए का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। गन्ना और कपास के वाजिब दाम नहीं मिलने पर जब किसान आत्महत्या करते हैं तो सरकार सोई रहती है। लेकिन जब होटल ताज पर हमला होता है तो सरकार की संवेदना तुरंत जागृत हो जाती है। उन्होंने कहा कि समाज से गैरबराबरी खत्म किए बिना सहअस्तित्व और सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि आज की राजनीति भी दिग्भ्रमित हो गई है। भारतीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था भी आजतक जातिविहीन नहीं हो पाई है। व्यक्ति की पहली आवश्यकता जाति नहीं रोटी, कपड़ा और मकान है। जब व्यक्ति की इन प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो उन्हें जाति के जाल में उलझाया जाता है। उन्होंने गांधी के विकास मॉडल को बेहतर मॉडल बताते हुए कहा कि समाज में शांति तभी कायम हो पाएगी जब शहरों की सुविधाओं को गांवों में ही मुहैया कराया जाएगा।

सबसे पहले सत्र को संबोधित करते हुए एम.पी. परमेश्वरन ने सामाजिक मूल्यों में आ रहे बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारा समाज रसातल में खुद जा रहा है। व्यक्ति अपने लालच को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन कर रहा है। जिससे व्यक्ति ने विकास तो कर लिया है लेकिन विकास ही मानवता के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आने वाले दिनों में सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे-प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि समाप्त हो जाएंगे और इसका खामियाजा आनेवाली पीढ़ी को भुगतना होगा । इसलिए आवश्यकता है कि समाज में जरूरत और लालच को समझा जाए ताकि मानवता के भविष्य को संरक्षित किया जा सके। उन्होंने विश्व भर में किए जा रहे विभिन्न समझौतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि क्योटो प्रोटोकाल, कोपेनहेगेन और डरबन की बैठक में चिंता जताने से इस समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

हिंदी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रख्यात पत्रकार प्रो. रामशरण जोशी ने कहा कि व्यक्ति यदि नैतिकतावादी होने के लिए सोचे भी तो समाज की व्यवस्था उसे नैतिक नहीं रहने देती है। एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी और भूख से बेहाल हैं वही दूसरी ओर दुनिया में खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे असमानता के बीच न्यायपूर्ण व्यवस्था की कल्पना करना बेमानी है। भारत के संदर्भ में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ६० करोड़ लोग बमुश्किल २० से ३२ रूपए पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं वही दूसरी ओर करोड़पतियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

इस असमानता को उन्होंने राजकीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए २६ सूत्रीय सुझाव दिए। जिसके तहत उन्होंने संपूर्ण निरस्त्रीकरण करने, विश्व सरकार की स्थापना, युद्ध को मानव विरोधी घोषित करना, हाशिए के लोगों की रक्षा और अंतरजातीय संघों की समाप्ति पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता जताई। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में प्रख्यात सामाजिक नेता विनायक सेन ने कहा कि तीसरी दुनिया में विकास किए बिना शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कल्पना छलावा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूख से मौतें तीसरी दुनिया में होती है। इन मौतों के लिए जिम्मेवार प्रथम विश्व के लोग होते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान सच्चर कमिटी के रिपोर्टों के हवाले पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों में आज भी ज्यादातर लोग बिना छत के फुटपाथ पर जीवन यापन करते है। दूसरी ओर अमीरों के लिए सरकार आदिवासियों को घर विहीन कर उनके संसाधनों पर कारखाना लगाने के लिए स्वतंत्र कर देती है।

अधिवेशन के दूसरे सत्र में बुधवार को हिंदी विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन विभाग की प्राध्यापक प्रो. इलीना सेन ने गैरबराबरी के सिद्धांत को आदिवासियों की जीवनशैली के जरिए समझाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं से व्यक्ति काफी सीख सकता है। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में व्यक्ति उनकी संस्कृति को अपनाना नहीं चाहता है। कई प्रमाणों में आदिवासियों की जीवनशैली सही होने के बावजूद उसे नकारा गया है। जहां एक तरफ तथाकथित सभ्य समाज में महिलाओं को बराबरी के लिए लड़ना पड़ रहा है। वही आदिवासी समाज में महिलाओं को पहले से ही समानता का अधिकार प्राप्त है। इस दौरान प्रो. सुनील वाजपेयी, डा. एम.एन मजूमदार, के.एस. राव ने संबोधित किया। इस सत्र की अध्यक्षता जे.एन.यू के प्राध्यापक पी.एस. रामकृष्णन ने की ।

गौरतलब है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ३५ वें सामाजिक विज्ञान का अधिवेशन चल रहा है। यह अधिवेशन ३१ दिसंबर तक चलेगा । इसके लिए देश के हर हिस्से से ३०० से ज्यादा समाज विज्ञानियों का जमावड़ा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के गांधी हिल्स पर लगा है।

बी एस मिरगे, जनसंपर्क अधिकारी